

दक्षिण एशिया में चीन की विकास परियोजनाओं से पर्यावरण को पहुंचेगा नुकसान, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

नई दिल्ली। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत गिलगित बाल्टिस्तान में राजमार्गों, इमारतों और बांधों का निर्माण कर रहा है। विशेषज्ञों ने इनके निर्माण पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञ मायरा मैकडोनाल्ड ने कहा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह पाकिस्तान से होकर हिमालय से भी गुजरता है।

दक्षिण एशिया क्षेत्र में चल रही चीन की विकास परियोजनाएं जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। जिसपर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। गरीबी उन्मूलन, विकास संगठन और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए यूरोपीय फाउंडेशन (ईएफएसएएस) की तरफ से मंगलवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र



मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र का आयोजन किया गया। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत गिलगित बाल्टिस्तान में राजमार्गों, इमारतों और बांधों का निर्माण कर रहा है। विशेषज्ञों ने इनके निर्माण पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञ मायरा मैकडोनाल्ड ने कहा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह पाकिस्तान से होकर हिमालय से भी गुजरता है। यह एक विवादित क्षेत्र भी है। मायरा का मानना है कि गिलगित बाल्टिस्तान को खत्म होने का बड़ा खतरा है क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही जलवायु परिवर्तन से पीड़ित है और भूगर्भीय रूप से अस्थिर है। ब्रिटिश

रक्षा मंत्रालय, एसआईपीआरएल और आरयूएसआई के लिए काम करने वाले ईएफएसएएस के एक रिसर्च फेलो टिम फॉक्सले ने कहा, तालिबान सरकार के साथ चीन घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने क्षेत्र से तेल और खनिजों का पता लगाने के इरादे पर प्रकाश डालते हुए कहा, चीन ने जनवरी में उत्तरी अफगानिस्तान में पेट्रोल की खोज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही वह लोगार प्रांत में तांबे की खदान के लिए चीन तालिबान के संपर्क में है। अनिवार्यता से बड़ी परियोजनाएं वनों की कटाई, जनसंख्या के विस्थापन, जल और मृदा प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाती हैं।



पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष के समाधान के लिए चौदह दिशा-निर्देश जारी किए

भोपाल। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारत में मानव तथा वन्यजीवों के संघर्ष की प्रभावी और कुशल रोकथाम के बारे में प्रमुख हितधारकों के बीच साझा समझ विकसित करना है। ये दिशा-निर्देश भारत-जर्मनी सहयोग परियोजना के अंतर्गत परामर्श के रूप में विकसित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में मानव और वन्यजीव विशेष रूप से हाथी, तेंदुआ, सांप और मगरमच्छ जैसे जीवों का मनुष्यों के साथ संघर्ष रोकने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

भारत दुनिया को बता सकता है कि जल प्रबंधन को कैसे नया रूप दिया जाए- सुनीता नारायण



लखनऊ। लखनऊ में विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण। लखनऊ में विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण। लखनऊ में विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस के मौके पर बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है, मगर भारत पहले से ही इस मामले में जमीन पर वास्तविक कार्रवाई कर रहा है। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा परिवर्तन संभव है। और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा सभी के लिए टिकाऊ और समावेशी

स्वच्छता और पानी प्रदान करने की चुनौती से निपटने के तरीके से स्पष्ट है। सुनीता नारायण लखनऊ में विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। उनका कहना है कि भारत दुनिया को बता सकता है कि जल प्रबंधन को कैसे नया रूप दिया जा सकता है। इस मौके पर नारायण ने कहा कि भारत का अनुभव दुनिया को यह सिखाने में अमूल्य रहा है कि कैसे जल प्रबंधन को फिर से खोजा जा सकता है, जो सस्ता और टिकाऊ हो। उन्होंने भारतीय तरीका के बारे में बताते हुए कहा, समुदायों को पानी का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो रिचार्ज और पुनरुत्पयोग पर केंद्रित हो। साथ ही उन्होंने

कहा कि पानी के प्रबंधन में सभी की जिम्मेदारी ही समाधान है। यह एक अवसर है। इस दशक में हमने जो भी सीखा है, उन्हें व्यवहार में लाकर भारत की पानी की कहानी पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पानी के प्रबंधन में सभी की जिम्मेदारी ही समाधान है। यह एक अवसर है। इस दशक में हमने जो भी सीखा है, उन्हें व्यवहार में लाकर भारत की पानी की कहानी पूरी कर सकते हैं। नारायण ने बताया कि आज के जलवायु-जोखिम वाली दुनिया में यह और भी महत्वपूर्ण है। हमें न केवल एक और बारिश बल्कि दूसरी और बाढ़ का सामना करने के लिए जल प्रणालियों में निवेश करने और उन्हें टिकाऊ बनाने के अपने काम को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने काम में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे

यहां कम दिनों में अधिक बारिश होगी। इसका मतलब यह है कि बारिश जब भी और जहां भी हो, उसे इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, ताकि उससे भूजल रिचार्ज हो सके। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए, पानी की कमी कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सावधानीपूर्वक उपयोग और उचित वितरण मुद्दा है। हम अपने जल संसाधनों का प्रबंधन

कैसे करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि हम गरीब रहेंगे या अमीर; रोगी रहेंगे या स्वस्थ। दूसरे शब्दों में, पानी हमारे भविष्य का निर्धारक है। जल प्रबंधन रणनीतियों को सावधानीपूर्वक बनाने की आवश्यकता होगी ताकि वे वितरित धन सृजन की ओर अग्रसर हों। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां के 95 प्रतिशत शहर व टाउन पूरी तरह से बिना सीवर सिस्टम पर निर्भर हैं। 737 में से केवल 31 कस्बों में कुछ हद तक सीवरेज सिस्टम है, जो इन कस्बों से निकलने वाले सीवेज के महज 40 प्रतिशत हिस्से को ट्रीट करता है। सीएसई के कार्यक्रम निदेशक (जल) देपिंदर कपूर कहते हैं, यही कारण है कि मल कीचड़ और सेप्टेज का सतत व समावेशी वैज्ञानिक प्रबंधन उत्तर प्रदेश के लिए प्राथमिकता है। राज्य के गरीब काफी हद तक ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों पर निर्भर हैं।

ऐसे में एक असरदार और सस्ती सीवेज प्रबंधन प्रणाली देने से सामाजिक, पर्यावरणीय और सावर्जनिक स्वास्थ्य के मामले में बेहतर परिणाम आएंगे। इसके अलावा सीएसई के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक (जल) सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा, उत्तर प्रदेश सभी के लिए समावेशी स्वच्छता को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।

एक सेप्टेज प्रबंधन नीति यहां लागू है। 59 कस्बों और शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्रणाली स्थापित की जा चुकी है तथा सीएसई के सहयोग से बिजनौर और चुनार के कस्बों में मल कीचड़ व ट्रीटमेंट प्रणाली काम कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन व शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात, उत्तर प्रदेश के एसबीएम की स्टेट मिशन डायरेक्टर नेहा शर्मा, उत्तर प्रदेश में अमृत के स्टेट मिशन डायरेक्टर रंजन कुमार, उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) के प्रबंध निदेशक अनिल ढिंगरा, ओडिशा जलापूर्ति व सीवरेज बोर्ड के इंजीनियर इन चीफ प्रशांत के महापात्र आदि मौजूद थे।

एयर क्लाइटी ट्रैकर- बारिश के बाद सुधरी वायु गुणवत्ता, दिल्ली सहित 119 शहरों में दर्ज की गई संतोषजनक

मुंबई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 21 मार्च 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 200 शहरों में से 50 में हवा बेहतर रही, जबकि 119 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, वहीं 30 में मध्यम रही। केवल झूंझूनू (205) में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया। यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्लाइटी इंडेक्स 75 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्लाइटी इंडेक्स 127, गाजियाबाद में 63, गुरुग्राम में 71, नोएडा में 72, ग्रेटर नोएडा में 68 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के संतोषजनक स्तर को दर्शाता है। जबकि लखनऊ में यह इंडेक्स 78, चेन्नई में 48, चंडीगढ़ में 66, हैदराबाद में 93, जयपुर में 68 और पटना में 117 दर्ज किया गया।

रिए पेपरजल की कमी से जूझ रहे हैं दुनिया के दो अरब लोग

नई दिल्ली। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, एक ऐसा दिन जो पानी से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्पित है। पानी से संबंधित समस्याओं का सामना लगभग हर देश के लोगों द्वारा किया जाता है। विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया एक अहम दिन है।

पानी जीवन के सभी पहलुओं के लिए अहम है। यह मानव स्वास्थ्य और कल्याण, ऊर्जा और खाद्य उत्पादन, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु अनुकूलन, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य आदि के लिए आवश्यक है। पानी सतत विकास के मूल में है। सुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंच एक मानव अधिकार है - हर किसी के स्वास्थ्य, गरिमा और समृद्धि के लिए अहम है। फिर भी, दुनिया भर में अरबों लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी है। विश्व जल दिवस 2023 अभियान जारी है। इस वर्ष, संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण का ध्यान जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए बदलाव में तेजी लाने पर है। बी द चेंज नामक वैश्विक अभियान लोगों को अपने जीवन में पानी के उपयोग, उपभोग और प्रबंधन के तरीके को बदलने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6-2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता को पूरा करने के लिए हम अभी भी बहुत दूर हैं। अरबों लोग और अनगिनत स्कूलों, व्यवसायों, स्वास्थ्य केंद्रों, खेतों और कारखानों के पास सुरक्षित पानी और शौचालय नहीं हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अनुमानित 78 करोड़ लोग स्वच्छ, सुलभ पेयजल के बिना रहते हैं। दूषित पानी पीने से कई जानलेवा



बीमारियां हो सकती हैं। यह दुनिया की तीसरी समस्या की तरह है, लेकिन फिलंट, मिशिगन ने हमें दिखाया कि पानी की समस्याओं का अमेरिका जैसे विकसित देश को भी परेशान करती है।

जल प्रदूषण वन्यजीवों को प्रभावित करता है- यह केवल मनुष्य ही नहीं है जिन्हें स्वच्छ जल तक पहुंच की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के कारण हर साल अनगिनत जानवरों की मौत हो जाती है। प्रदूषण कई तरह से हो सकता है, कचरे से लेकर अपशिष्ट जल और रसायनों के बहकर पानी में मिलने तक, जिसके कारण पानी उन जानवरों के लिए जहरीला हो जाता है जो पीने और रहने के लिए इस पर निर्भर होते हैं।

पानी कई अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है- विश्व जल दिवस की एक वार्षिक थीम है, जैसे जल के लिए

प्रकृति, जो हमारे जल संकट के प्राकृतिक समाधान खोजने के लिए समर्पित है। हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से कई आपस में जुड़ी हुई हैं - जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षण जल प्रदूषण, बाढ़ और सूखे से संबंधित हैं और कभी-कभी प्रत्यक्ष कारण भी इसके पीछे होते हैं।

क्या आप जानते हैं?- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषित पानी के उपयोग से हर साल 14 लाख लोगों की मौत होती है और 7.4 करोड़ लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, साफ-सफाई से जुड़ी बीमारियों के कारण लोगों का

जीवन काल छोटा हो जाता है। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 व्यक्ति तथा दुनिया भर में दो अरब लोग सुरक्षित पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आबादी का लगभग आधा 3.6 अरब लोग स्वच्छता की कमी में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र-जल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक, दुनिया भर में, 44 प्रतिशत घरेलू अपशिष्ट जल का सुरक्षित उपचार नहीं किया जाता है। दुनिया भर में पानी की मांग के 2050 तक 55 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। कुछ मित्रों को साथ लें और अपना स्वयं के पानी के स्रोतों की सफाई दल बनाएं। यह एक छोटा और महत्वहीन कदम लग सकता है, लेकिन कचरा वन्य जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा, आपके आस-पास की छोटी नदियां और नदियों के पानी के एक बड़े हिस्से में

जाने की संभावना है। यदि आप उस छोड़े गए कचरे को नहीं उठाते हैं, तो यह समुद्र में अपना रास्ता खोज सकता है और मछली या सीगल के लिए बहुत बुरी खबर बन सकता है।

अपने बॉटर फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश करें- ऐसा नहीं लग सकता है कि आप अपने रोजमरा के जीवन में बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि घरेलू कार्यों को करने में कितना पानी लगता है। औसत अमेरिकी शॉवर में लगभग 17 गैलन पानी का उपयोग होता है, जबकि एक शौचालय फ्लश में सात गैलन पानी का उपयोग होता है। यदि आप अपने दैनिक पानी के उपयोग को कम करने में रुचि रखते हैं, तो कई उत्पाद हैं - जैसे कम प्रवाह वाले शौचालय और शावर हेड, जो आपको ऐसा करने में मदद कर सकते हैं।

जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें- यदि आप एक भव्य और तत्काल प्रभाव देखना चाहते हैं, तो आप एक धर्मार्थ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। पूरे विश्व में, समुदाय विश्व जल दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप हमारे सामने आने वाली पानी से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

कैसे मिल सकती है जीवाश्म ईंधन से मुक्ति?

कोयला और प्राकृतिक गैस को अलग-अलग माने जाने का क्या औचित्य है, जबकि दोनों ही जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) हैं? यह सबाल मैंने पिछले लेख में उठाया था, क्योंकि यह जलवायु न्याय से जुड़ा मसला है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात पृथ्वी को गर्म बनाने के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन द्वारा होने वाले उत्सर्जन की गति और पैमाने की व्यवहार्यता की है। सच्चाई यह है कि मोटे तौर पर दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी वातावरण में उत्सर्जन की मात्रा के लिए किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आज अपनी उर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अमीर देशों ने आसानी के साथ कोयले की जगह प्राकृतिक गैस के विकल्प को अपना लिया है, जो कि अपेक्षाकृत एक स्वच्छ ईंधन है। मीठेन के अतिरिक्त यह मोटे तौर पर कोयले द्वारा किए जाने वाले उत्सर्जन के मुकाबले आधी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित करता है। लेकिन ऊर्जा के प्रति इन देशों के अतिलोभ को देखते हुए यह आसानी से समझा जा सकता है कि अतीत और वर्तमान में इनके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्सर्जन किया जाता रहा है। वैश्विक कार्बन बजट में उनकी भागेदारी को देखते हुए यह स्थिति पूरी तरह से गैर आनुपातिक है। अब स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प को चुनने का दबाव कमोबेश उन देशों के ऊपर है, जो न केवल उत्सर्जन के लिए कम जिम्मेदार हैं, बल्कि इस विकल्प को अपनाने में बहुत सक्षम भी नहीं हैं। यह स्थिति अनुचित होने के साथ-साथ असंगत भी है और यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध युद्ध को कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है। वर्तमान वैश्विक प्रयास वस्तुतः दोतरफा हैं। पहला, दक्षिण के देशों की उन ताप विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना बंद करना होगा, जो कोयले पर निर्भर हैं। दूसरा, कोयले पर निर्भर हैं। यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध युद्ध को कहीं अधिक मदद करनी होगी। जी-7 देशों के जस्त एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेर्टी-पी) में अब दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम भी शामिल हैं, लेकिन जूरी अभी भी इसको लेकर स्पष्ट नहीं है कि इस बदलाव को वास्तविकता में बदलने के लिए जेर्टी-पी आवश्यक वित्तीय मदद देगी अथवा नहीं। सौर और पवन ऊर्जा के मूल्य में आई गिरावट के बाद भी आज कोयले पर निर्भर नई परियोजना की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा की एक नई परियोजना का निर्माण दो से तीन गुना अधिक महंगा है।



बच्चों ने एकेडमिक फेयर में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश, साइंस के मॉडल्स बने चर्चा

गाजियाबाद. यूपी के गाजियाबाद के नारायण ई-टेक्नो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट और कम्प्युनिकेशन स्किल्स जैसे कौशल सिखाने के लिए बच्चों द्वारा एकेडमिक फेयर का आयोजन किया गया है। इस फेयर में नहें- मुन्हों बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनको देखने के लिए उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया है। बच्चे साइंस मॉडल हो या ईवीएम मशीन सबके बारे में प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं।

अगस्त्य विक्रम सिंह ने पर्यावरण को बचाने के लिए मॉडल बनाया था। लोकल को उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है पेड़ बचाने से जीवन बचता है। आजकल पेड़ों को काटने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, जिस कारण से मनुष्यों को ही इसे जूझना होगा। हम ये संदेश दे रहे हैं कि वृक्षारोपण करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटने से बचाएं।

विभिन्न विषय की समझ बढ़ाने का किया प्रयास

क्लास 5 की शिक्षक दिव्या बंसल ने बताया कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक हफ्ते का टाइम दिया गया था, जिसमें सब्जेक्ट वाइज इनको विषय दिया गए थे। इसके पीछे का मकसद था इन बच्चों की समझ को बढ़ाना। इसमें कुछ साइंस के मॉडल्स से थे, कुछ ऐतिहासिक ईमारों के, कुछ सामाजिक मुद्दे और कुछ पर्यावरण से जुड़े मुद्दे थे। इस फेयर के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ।

किताबी ज्ञान के अलावा भी जरूरी है स्किल्स को अपनाना

नारायण ई-टेक्नो स्कूल की प्रधानाचार्य योगिता कपिल ने बताया कि इस एकेडमिक फेयर में नर्सरी से ले कर पांचवीं क्लास तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इन बच्चों की काफी समझ बढ़ी। नर्सरी के बच्चों ने भी अपने मॉडल्स के बारे में बताया जिसे किताब के जरिए समझने में उन्हें काफी समय लग जाता। कम्प्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, टीम स्पिरिट जैसी चीजें इन बच्चों ने सीखी हैं।

कई चुनौतियों का सामना कर रहीं हैं कार्बन कैप्चर तकनीकें

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुसार, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) को लागू करने की राह में कई बाधाएं हैं। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीकों को जलवायु शमन के एक उपकरण के रूप में भी जाना जाता है, जो वातावरण में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है।

इन सभी पहलुओं को उजागर करते हुए आईपीसीसी ने 20 मार्च 2023 को अपनी नई संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के रास्ते में मौजूद तकनीकी, आर्थिक, संस्थागत, पारिस्थितिक, पर्यावरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। लेखकों का इस बारे में विचार है कि, नीतिगत उपकरण, अधिक सार्वजनिक समर्थन और तकनीक में नवीनता आदि की मदद से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। देखा जाए तो वातावरण से अतिरिक्त कार्बन को सोखने को दो तरीके हैं पहला प्राकृतिक तरीका है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, वेटलैंड आदि का समर्थन करना आदि शामिल है जो प्राकृतिक तौर पर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इन्हें प्राकृतिक सिंक भी कहा जाता है। वहीं दूसरे तरीके में इसके लिए तकनीकों की मदद ली जाती है।

'कार्बन कैप्चर और स्टोरेज' इसी को कहते हैं इसमें नवीनतम तकनीकों की मदद से वातावरण में मौजूद कार्बन को एकत्र करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। देखा जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ने से पहले ही कैप्चर और स्टोर करने की प्रक्रिया है। इस

प्रक्रिया में तकनीकों की मदद से वातावरण या अन्य उत्सर्जन स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, उसका परिवहन और फिर उसे उपयुक्त गहराई या खनिजों में स्टोर करना शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन में इंजेक्ट या स्टोर करने के ऐसे ही एक विकल्प को एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी (ईओआर) कहा जाता है। यह तकनीक तेल और गैस उद्योगों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) में एनर्जी सप्लाई यूनिट के प्रमुख क्रिस्टोफ मैकगलाडे का कहना है कि, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) आँयल रिजर्व के कुल दबाव को बढ़ा देती है। नतीजन मौजूद तेल, उत्पादन कुओं की ओर जाने लगता है। उनके अनुसार इंजेक्ट किया गया सीओ2 तेल के साथ मिल सकता है, जिससे उसे बहने में मदद मिलती है। आईईए के एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी परियोजनाओं के नए वैश्विक डेटाबेस से पता चला है कि, आज इस तकनीक की मदद से हर दिन करीब 5,00,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे वातावरण (डीएसीसीएस) या बायोमास (बीईसीसीएस) से कैप्चर किया जाता है तब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीकों सीओ2 हटाने के तरीकों के लिए भंडारण घटक प्रदान करती हैं। हालांकि यह सीसीएस तकनीकें बिजली, सीमेंट और केमिकल उत्पादन के लिए अभी उतनी परिपक्व नहीं हैं, जहां इसे जलवायु शमन के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाता है। वहीं सेंटर फॉर इंसेशनल एनवायरनमेंटल लॉकी उपनिदेशक लिली फुहर का कहना है कि अधिकांश मौजूदा सीसीएस

परियोजनाएं, एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी यानी ईओआर परियोजनाएं हैं, जो तेल उत्पादन तो कर रही हैं, लेकिन उत्सर्जन को कम नहीं करती। उनके अनुसार वर्तमान में वो वैश्विक उत्सर्जन के 0.1 फीसदी से भी कम हिस्से को कैप्चर कर रही हैं। उनके अनुसार देखा जाए तो यह जीवाश्म ईंधन कंपनियां, इस तकनीक का उपयोग एक आवरण के रूप में कर रही हैं, क्योंकि वे इसकी आड़ में अपने व्यापार का बढ़ाना चाहती हैं। सेंटर फॉर इंसेशनल एनवायरनमेंटल लॉकी के मुताबिक सीसीएस तकनीकें एक उत्सर्जक स्रोत, जैसे सीमेंट संयंत्र से उत्सर्जन के एक हिस्से को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हटाने (सीडीआर) की तकनीकें कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से ही वातावरण में भंडारण के किसी न किसी रूप में स्थानांतरित कर देती है।

ऐसे में रिपोर्ट का कहना है कि शुद्ध-नकारात्मक उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीडीआर तकनीकें जरूरी हैं। यदि तापमान में होती वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाती है तो रिपोर्ट का सुझाव है कि ऐसे में अतिरिक्त सीडीआर की तैनाती जरूरी है।

इतना ही नहीं सीडीआर की मदद से कृषि, उड्डयन, नौकरी और औद्योगिक प्रक्रियाओं से होने वाले उत्सर्जन का मुकाबला किया जा सकता है। इसकी मदद से शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हालांकि, रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और लोगों के लिए सीडीआर को लागू करने के प्रभाव, जोखिम और सह-लाभ अत्यधिक परिवर्तनशील होंगे। जो इसके स्थान, तरीकों और पैमाने पर निर्भर करेंगे।